

वर्ष-15, अंक-329

पृष्ठ-8 मूल्य 2 रुपया

महान लोग सदैव स्वर्य की खोज में  
दहरते हैं। जिस ज्ञान से मनुष्य स्वर्य  
को जान सके वही सच्चा ज्ञान है।

CITYCHIEFSENDMENNEWS@GMAIL.COM

# मिटी चीफ

इंदौर, बुधवार 05 मार्च 2025

सम्पूर्ण भारत में चर्चित हिन्दी अखबार



हाईकोर्ट का मध्यप्रदेश सरकार से सवाल...

## सरकार ने डीजे पर बैन लगाने लिए क्या कार्रवाई की?

जबलपुर। मध्यप्रदेश में डीजे की कानफोड़ा आवाज के कारण लोगों की मौत की कई खबरें आ चुकी हैं। अब मप्र हाईकोर्ट डीजे पर बैन लगाने को लेकर मध्यप्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। राज्य सरकार को जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है। उच्च न्यायालय ने पूछा है कि तेज आवाज में बज रहे डीजे पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? क्या कोई डायरेक्शन निर्धारित किए हैं? डीजे की आवाज कितनी होना चाहिए? रद्द करने के लिए आवाज का अमिताभ गुप्ता ने हाईकोर्ट में इस संबंध में जनहित याचिका दायर की थी। मंगलवार को चीफ जस्टिस सुशेश कुमार कैट और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बैंच ने सुनवाई की है। अधिकारी अमिताभ गुप्ता ने याचिका में कहा कि इन दिनों हर कार्यक्रम में तेज आवाज में डीजे बजाने का पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही सामाजिक समरसता के लिए भी घातक है। डीजे के प्रयोग से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जिसके चलते लोग बीमार हो रहे हैं। इन्हाँने ही नहीं समाज में डीजे के कारण ही तनाव फैल रहा है और इसकी आवाज से दंगे-फसाद हो



रहे हैं।

तेज आवाज से होने वाली बीमारी का इलाज नहीं याचिकाकार्त का कहाना है कि तेज आवाज से होने वाली बीमारी का इलाज भी नहीं है। सुनवाई के दौरान याचिकाकार्त ने कोर्ट रूम में भी बाकायदा मोबाइल एप से साउंड पॉल्यूशन रिकार्ड कर प्रैविक्टल करते हुए कोर्ट को बताते हुए कहा कि यहां पर शार्टपूर्ण ढंग से सुनवाई हो रही है, बहस चल रही है, तब भी ध्वनि का पैरामीटर 60 डेसिबल राहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जब सड़क पर तेज आवाज में डीजे बजता है, तो यही डेसिबल कितना होगा।

भोपाल में जा चुकी है 13 वर्षीय किशोर की जान एडवोकेट अमिताभ गुप्ता ने याचिका में भोपाल के एक मामले का भी काज जिक्र किया।

रीवा में बस पर पथराव, पत्थर लगाने से इंदौर के डॉक्टर की मौत

हादसा या हत्या?

## रीवा में बस पर पथराव, पत्थर लगाने से इंदौर के डॉक्टर की मौत



इस मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस अजात बदमाशों ने बस पर अचानक पथराव कर दिया। इस घटनाक्रम में बस में यात्रा कर रहे इंदौर के डॉक्टर के सिप पर एक बड़ा पत्थर लग गया। गंभीर हालत में उहें संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान डॉक्टर की मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस माला कर उनकी तलाश में जुट गयी है। पुलिस सूर्तों के अनुसार रीवा से इंदौर जा रही इंटरसिटी यात्री बस सेवावार शाम चोरहटा थाना क्षेत्र के सप्तपुड़ा आईटीआई के सामने पहुंची, तभी मोटर साइकिल से आए तीन अज्ञात बदमाशों ने बस पर अचानक पथराव कर दिया। इस घटना में बस सवार एक यात्री डॉ. हीरामणि कोरी की मौत हो गई। घटना के बाद अज्ञात बदमाश मौके से फरार हो गए। वहाँ, बस चालक को भी इस घटनाक्रम में चोट आयी है, जिसे अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने

शब लेने से इनकार कर दिया। उहने कहा कि मेरे बेक्सर पति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मैं तब तक शब नहीं लूंगी। जब तक आरोपियों पर कठोर कार्रवाई नहीं की जाती। डॉ. हीरामणि के सहकर्ता गाहुल सिंह ने बताया कि वे दो बच्चों के पिता हैं। उनका एक 5 साल का बेटा और 2 साल की बच्ची है।

### मप्र ने विकास प्राधिकरण शहर के बाहर भी कर सकेंगे विकास कार्य

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को भौतिक और प्रौद्योगिकी के बैठक हुई। इसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। कैबिनेट मंत्री कैलेश विजयरायने ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर एवं ग्राम निवेश की धारा 60 में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत अब सरकार के प्राधिकरण जैसे बीडीए, आईटीएलाइन एरिया के बाहर रोड, पुल, पुलिया समेत अन्य विकास कार्य समेत कोलोनियां काट सकेंगे। वहीं, साडा शहर के अंदर एवं खुद और आपसमें के डुबकी लागवाना चाहता हूं। हमारे सभी तीज-त्योहार अहम हैं। इन

भोपाल। मध्यप्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। वजह है विजली बचाने और प्रौद्योगिकी के बैठकों के लिए उनकी ओर से लिया गया स्थान कल्पना। उनके निवेश की धारा 60 में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत अब सरकार के प्राधिकरण जैसे बीडीए, आईटीएलाइन एरिया के बाहर रोड, पुल, पुलिया समेत अन्य विकास कार्य समेत कोलोनियां काट सकेंगे। वहीं, साडा शहर के अंदर एवं खुद और आपसमें के डुबकी लागवाना चाहता हूं। अब उनके निवेश की धारा 60 में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत अब सरकार के प्राधिकरण जैसे बीडीए, आईटीएलाइन एरिया के बाहर रोड, पुल, पुलिया समेत अन्य विकास कार्य समेत कोलोनियां काट सकेंगे। वहीं, साडा शहर के अंदर एवं खुद और आपसमें के डुबकी लागवाना चाहता हूं। अब उनके निवेश की धारा 60 में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत अब सरकार के प्राधिकरण जैसे बीडीए, आईटीएलाइन एरिया के बाहर रोड, पुल, पुलिया समेत अन्य विकास कार्य समेत कोलोनियां काट सकेंगे। वहीं, साडा शहर के अंदर एवं खुद और आपसमें के डुबकी लागवाना चाहता हूं। अब उनके निवेश की धारा 60 में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत अब सरकार के प्राधिकरण जैसे बीडीए, आईटीएलाइन एरिया के बाहर रोड, पुल, पुलिया समेत अन्य विकास कार्य समेत कोलोनियां काट सकेंगे। वहीं, साडा शहर के अंदर एवं खुद और आपसमें के डुबकी लागवाना चाहता हूं। अब उनके निवेश की धारा 60 में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत अब सरकार के प्राधिकरण जैसे बीडीए, आईटीएलाइन एरिया के बाहर रोड, पुल, पुलिया समेत अन्य विकास कार्य समेत कोलोनियां काट सकेंगे। वहीं, साडा शहर के अंदर एवं खुद और आपसमें के डुबकी लागवाना चाहता हूं। अब उनके निवेश की धारा 60 में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत अब सरकार के प्राधिकरण जैसे बीडीए, आईटीएलाइन एरिया के बाहर रोड, पुल, पुलिया समेत अन्य विकास कार्य समेत कोलोनियां काट सकेंगे। वहीं, साडा शहर के अंदर एवं खुद और आपसमें के डुबकी लागवाना चाहता हूं। अब उनके निवेश की धारा 60 में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत अब सरकार के प्राधिकरण जैसे बीडीए, आईटीएलाइन एरिया के बाहर रोड, पुल, पुलिया समेत अन्य विकास कार्य समेत कोलोनियां काट सकेंगे। वहीं, साडा शहर के अंदर एवं खुद और आपसमें के डुबकी लागवाना चाहता हूं। अब उनके निवेश की धारा 60 में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत अब सरकार के प्राधिकरण जैसे बीडीए, आईटीएलाइन एरिया के बाहर रोड, पुल, पुलिया समेत अन्य विकास कार्य समेत कोलोनियां काट सकेंगे। वहीं, साडा शहर के अंदर एवं खुद और आपसमें के डुबकी लागवाना चाहता हूं। अब उनके निवेश की धारा 60 में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत अब सरकार के प्राधिकरण जैसे बीडीए, आईटीएलाइन एरिया के बाहर रोड, पुल, पुलिया समेत अन्य विकास कार्य समेत कोलोनियां काट सकेंगे। वहीं, साडा शहर के अंदर एवं खुद और आपसमें के डुबकी लागवाना चाहता हूं। अब उनके निवेश की धारा 60 में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत अब सरकार के प्राधिकरण जैसे बीडीए, आईटीएलाइन एरिया के बाहर रोड, पुल, पुलिया समेत अन्य विकास कार्य समेत कोलोनियां काट सकेंगे। वहीं, साडा शहर के अंदर एवं खुद और आपसमें के डुबकी लागवाना चाहता हूं। अब उनके निवेश की धारा 60 में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत अब सरकार के प्राधिकरण जैसे बीडीए, आईटीएलाइन एरिया के बाहर रोड, पुल, पुलिया समेत अन्य विकास कार्य समेत कोलोनियां काट सकेंगे। वहीं, साडा शहर के अंदर एवं खुद और आपसमें के डुबकी लागवाना चाहता हूं। अब उनके निवेश की धारा 60 में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत अब सरकार के प्राधिकरण जैसे बीडीए, आईटीएलाइन एरिया के बाहर रोड, पुल, पुलिया समेत अन्य विकास कार्य समेत कोलोनियां काट सकेंगे। वहीं, साडा शहर के अंदर एवं खुद और आपसमें के डुबकी लागवाना चाहता हूं। अब उनके निवेश की धारा 60 में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत अब सरकार के प्राधिकरण जैसे बीडीए, आईटीएलाइन एरिया के बाहर रोड, पुल, पुलिया समेत अन्य विकास कार्य समेत कोलोनियां काट सकेंगे। वहीं, साडा शहर के अंदर एवं खुद और आपसमें के डुबकी लागवाना चाहता हूं। अब उनके निवेश की धारा 60 में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत अब सरकार के प्राधिकरण जैसे बीडीए, आईटीएलाइन एरिया के बाहर रोड, पुल, पुलिया समेत अन





## संपादकीय

## सार्वजनिक वित्तीय संसाधनों को प्रभावी ढंग से खर्च करना जरूरी

केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए प्राप्त राशि या राज्य के लिए आवंटित विशेष फंड के इस्तेमाल में कुछ राज्य सरकारों के स्तर पर हो रही गड़बड़ी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। वित्त मंत्रालय ने एसएनए-स्पर्श (समयोजित प्रणाली एकीकृत शीर्ष हस्तांतरण) नाम से लागू इस नई व्यवस्था के तहत राज्यों के फंड प्रवाप पर अब ज्यादा सतर नजर केंद्र सरकार रखा पा रही है। इस नई व्यवस्था में केंद्र सरकार के विभागों की भूमिका भी ज्यादा प्रभावशाली है।

और उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। इस नई व्यवस्था से केंद्र राज्यों के वित्त प्रबंधन पर इस हसाब से नजर रखी जा रही है कि कहीं किसी खास उद्देश्य से भेजे गये फंड का इस्तेमाल हुआ है या नहीं। भारत जैसे संघीय ढांचे और विकेंद्रीकृत व्यवस्था वाले विशाल देश में सार्वजनिक वित्तीय संसाधनों को किफायती और प्रभावी ढंग से खर्च किया जाना जरूरी है। अगर किसी योजना के लिए आवंटित रकम खर्च नहीं होती है तो उसे दूसरे बेहतर उद्देश्यों में खर्च किया जा सकता है ताकि बेहतर आर्थिक परिणाम मिल सके।

केंद्र सरकार कई केंद्र प्रायोजित योजनाएँ चलाती हैं, जिनके लिए धन विभिन्न खातों में भेजा जाता है और अक्सर इस्तेमाल हुए बौरे पड़ा रहता है। लेकिन नया मॉडल आने के बाद विश्वित बदल गई क्योंकि इसमें एकीकृत नेटवर्क के जरिये ऐन वक्त पर केंद्र तथा राज्य सरकारों से इकट्ठा धन

जारी किया जाता है। एक विश्लेषण के अनुसार इससे सरकारी खातों का काफी समेकन और कोषों का एकीकरण हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गत सप्ताह व्यवधानों और लेखा महानियंत्रक से यह सुनिश्चित करने को कहा कि आगे वित्त वर्ष से यह सभी योजनाओं के लिए।

एकल नोडल एजेंसी 'स्पर्श' शुरू कर दी जाए।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि लेखा महानियंत्रक राज्यों को

अन्य व्यवस्थाओं से इस मंच पर लाए और उन्हें इसके फायदों की जानकारी भी दे। अधिकांश केंद्रीय योजनाएँ पहले ही इस प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं और अनुमान है कि इसकी मदद से सरकार ने 2021-22 से अब तक 11,000 करोड़ रुपए से अधिक धन बचाया है। सरकारी व्यय को अधिक कारोबार बनाने के कई प्रत्यक्ष लाभ हैं। इससे समय पर रकम मिलना सुनिश्चित होता है। भारत में केंद्र सरकार और सभी राज्यों की सरकारों को राजकोषीय घाटा बढ़ाता है और अपने खर्च के लिए दोनों ही बाजार उत्तरी का सहारा लेती है। रकम इस्तेमाल नहीं होने का मतलब है कि सरकार ऐसे का उपयोग नहीं कर पाई मगर उस पर ब्याज चुकाएगी। इसलिए नकद प्रबंधन को बेहतर बनाने के उपाय अपनाना सही रहेगा इस बार के बजट में केंद्र सरकार ने पहली बार एकल नोडल एजेंसी वाले खातों की संख्या का ब्योरा दिया था। इससे पता चला कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के करीब 1 लाख करोड़ रुपए राज्यों के खाते में खर्च हुए बौरे पड़े हैं। इसमें से 45 फीसदी रकम तो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, जल जीवन मिशन, सक्षम अंगनवाड़ी और पोषण-4.0, शहरी कायाकल्प मिशन-500 शहर, और स्वच्छ भारत मिशन-शहरी में ही खर्च होने से रह गई। उदाहरण के लिए 2024-25 में 70,162 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे मगर इसमें से आधी रकम भी खर्च नहीं जा सकी। 2025-26 में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए आवंटन चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों से 7.2 फीसदी ज्यादा है। एकल नोडल एजेंसी खातों का ब्योरा ही दिखाता है कि पारदर्शिता कैसे बढ़ सकती है। राज्य अक्सर शिकायत करते हैं कि उन्हें पर्याप्त रकम नहीं भेजी जाती। मगर ब्योरा दिखाता है कि भेजी गई रकम भी अक्सर खर्च नहीं हो पाती। ही सकारा है कि वाजिब बजहें हों और बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए ये बजहें जाना जरूरी है। समूचे सरकारी व्यय कितना कारगर रहा इसकी पड़ताल करते समय इस बात पर बहस होनी चाहिए कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या कम करने की जस्तरता तो नहीं है। चूंकि राज्यों को भी संसाधन खर्च करने होते हैं, इसलिए संभव है कि उन्हें तंगी महसूस होती हो और वे धन को बहाने पहले खर्च करना चाहते हों, जहां उनकी जनता को ज्यादा पायदा होता है। राज्य अक्सर ठोस बजहों के साथ कहते हैं कि केंद्र से उन्हें बिना रुके रकम नहीं रहनी चाहिए किंतु इससे उन्हें अपनी जस्तरत के हिसाब से कार्यक्रम बनाने की छूट मिल जाती है। इस मामले में एकदम सटीक संतुलित बनाने की सिफारिश वित्त अयोग से आनी चाहिए।

वित्त वर्ष के लिए जल जीवन मिशन के लिए 2024-25 में 70,162 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिनमें उन्हें तंगी संसाधन खर्च करने के साथ कहते हैं कि उन्हें बिना रुके रकम नहीं रहनी चाहिए किंतु इससे उन्हें अपनी जस्तरत के हिसाब से कार्यक्रम बनाने की छूट मिल जाती है। इस मामले में एकदम सटीक संतुलित बनाने की सिफारिश

किए गए थे मगर इसमें से आधी रकम भी खर्च नहीं जा सकी।

सकी। 2025-26 में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए आवंटन चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों से 7.2 फीसदी ज्यादा है। एकल नोडल एजेंसी खातों का ब्योरा ही दिखाता है कि पारदर्शिता कैसे बढ़ सकती है। राज्य अक्सर शिकायत करते हैं कि उन्हें पर्याप्त रकम नहीं भेजी जाती। मगर ब्योरा दिखाता है कि भेजी गई रकम भी अक्सर खर्च नहीं हो पाती। ही सकारा है कि वाजिब बजहें हों और बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए ये बजहें जाना जरूरी है। समूचे सरकारी व्यय कितना कारगर रहा इसकी पड़ताल करते समय इस बात पर बहस होनी चाहिए कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या कम करने की जस्तरता तो नहीं है। चूंकि राज्यों को भी संसाधन खर्च करने होते हैं, इसलिए संभव है कि उन्हें तंगी महसूस होती हो और वे धन को बहाने पहले खर्च करना चाहते हों, जहां उनकी जनता को ज्यादा पायदा है। तमिलनाडु इसे सविधान का अपमान और विंदी थोपने का प्रयास बता रहा है। मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय वित्तीय राज्यों को उन्होंने लिया है कि उन्हें बिना रुके रकम नहीं रहनी चाहिए किंतु इससे उन्हें अपनी जस्तरत के हिसाब से कार्यक्रम बनाने की छूट मिल जाती है। इस मामले में एकदम सटीक संतुलित बनाने की सिफारिश वित्त अयोग से आनी चाहिए।

वित्त वर्ष के लिए जल जीवन मिशन के लिए 2024-25 में 70,162 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिनमें उन्हें तंगी संसाधन खर्च करने के साथ कहते हैं कि उन्हें बिना रुके रकम नहीं रहनी चाहिए किंतु इससे उन्हें अपनी जस्तरत के हिसाब से कार्यक्रम बनाने की छूट मिल जाती है। इस मामले में एकदम सटीक संतुलित बनाने की सिफारिश

# देश में हर चार मिनट में होती है सड़क पर एक मौत



जीवन के सबसे बड़े सत्य का नाम मृत्यु है जिसे कोई नहीं रोक सकता। यह ऐसा सत्य है जिसकी कल्पना मात्र से मरने वाला ही नहीं बल्कि उसके प्रियजनों की भी रुह कांप जाती है। यह मृत्यु तब और अधिक भयंकर हो जाती है जब किसी की असाधारण मृत्यु हो जाए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार वर्ष 2022 में कुल 7,00,688 दुर्घटनाएँ रिपोर्ट की गई, जिनमें 4,22,444 लोगों की मृत्यु हुई और 4,28,435 लोग घायल हुए। इनमें 46 प्रतिशत असाधारण मौतें यातायात हादसों में हुई हैं। हालांकि, भारत सरकार और राज्य सरकारों की ओर से इन हादसों पर नियंत्रण के लिए कई स्तरों पर प्रयत्न किए जा रहे हैं। सन् 2001 से पूरे जनवरी के महीने में सड़क सुरक्षा माह भी मनाया जा रहा है, लेकिन ये हादसे हैं कि घटने के बायाकाले जारी होते हैं। इस गंभीर समस्या की ओर एक बार फिर से ध्यान आकर्षित करते हैं।

विश्व बैंक की 2021 में आई एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत में दुनिया के एक प्रतिशत वाहन तक हैं लेकिन सड़कों पर प्रयास किए जा रहे हैं। देश में हर घंटे 53 सड़क दुर्घटनाएँ हो रही हैं और हर चार मिनट में एक मौत होती है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार यह पिछले एक दशक में भारतीय सड़कों पर 13 लाख लोगों की मौतें हुई हैं इनके अलावा 50 लाख लोग घायल हुए हैं।

रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं के चलते 5.96 लाख करोड़ रुपये यानी सकल घेरे-लू उत्पाद (जीडीपी) के 3.14 प्रतिशत के बराबर नुकसान होता है। भारत में आक्सिमिक मौतें में सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतें का आंकड़ा 15 प्रतिशत से लेकर 20 प्रतिशत तक शुमार होता है, जो एक चिंता का विषय है। एनसीआरबी के अनुसार, सड़क दुर्घटनाओं के चलते भारत में होती हैं। देश में हर घंटे 53 सड़क दुर्घटनाएँ हो रही हैं और हर चार मिनट में एक मौत होती है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार यह स्थरों और ग्रामीण क्षेत्रों में हुई मौतें का अंकड़ा 15 प्रतिशत से लेकर 20 प्रतिशत तक शुमार होता है, जो एक चिंता का विषय है। एनसीआरबी के अनुसार, सड़क दुर्घटनाओं के चलते भारत में होती हैं। देश में हर घंटे 53 सड़क दुर्घटनाओं के चलते भारतीय सड़कों पर 13 लाख लोगों की मौतें हुई हैं इनके अलावा 50 लाख लोग घायल हुए हैं।

रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं के चलते 5.96 लाख करोड़ रुपये यानी सकल घेरे-लू उत्पाद (जीडीपी) के 3.14 प्रतिशत के







# खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा आतंकी हमला

आर्मी कैंट इलाके में बम धमाके में 9 की मौत, 35 घायल

इस्लामाबाद, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित बनू कैटोनमेंट के बाहरी इलाके में दो भीषण बम धमाके हुए, धमाकों के बाद इलाके में भारी गोलीबारी और सुरक्षावलों व आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। इसे एक पूर्व नियोजित आतंकी हमला बताया जा रहा है।

न्यूज एंजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, सुरक्षा बलों और हमलावारों के बीच हुई झड़प में कम से कम नौ लोग मारे गए और 35 घायल हो गए। जैश उल फूरसान, जो किसी समय पर पाक सेना गठबंधन का हिस्सा रहे (हाफिजु गुल बहादुर) का हिस्सा है और जिसने हाल ही में टीटीवी के साथ हाथ मिलाया है, इस हमले के पीछे बताया जा रहा है।

## आतंकियों ने किया कार

### बम का इस्तेमाल

रिपोर्ट के अनुसार, आतंकियों ने दो कार बम का इस्तेमाल किया, ताकि सुरक्षा बलों का ध्यान भटकाया जा सके।



संकेत, इसके तुरंत बाद टारेट हमला किया गया। आतंकियों ने इसपर फैले सोमवार को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक महिला सुसाइड बॉम्बर ने फॉटियर कार के काफिले को निशाना बनाया था। इस हमले में एक सैनिक की मौत हो गई थी जबकि चार अन्य घायल हो गए।

### सुसाइड अटैक

इससे फैले सोमवार को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक महिला सुसाइड बॉम्बर ने फॉटियर कार के काफिले को निशाना बनाया था। इस हमले में एक सैनिक की मौत हो गई थी जबकि चार अन्य घायल हो गए।

**बलूचिस्तान में हुआ था**

## बोफोर्स घोटाले की जांच को फिर से शुरू करने के संकेत

भारत सरकार ने अमेरिका से मांगी नई जानकारी



नई दिल्ली। भारत ने अमेरिका को एक अनुरोध भेजा है, जिसमें 64 करोड़ रुपये के बोफोर्स घोटाले से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी की मांगी गई है। भारत सरकार के इस नए कदम से स्वीडन से 155 मिमी फौल्ड एस्टिलियर गन्स की खरीद को लेकर राजीव गांधी की अगुवाई वाली कंप्रेस सरकार के तहत हुए इस घोटाले की जांच को फिर से शुरू करने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा है कि सीबीआई ने हाल ही में एक विशेष अदालत द्वारा जारी पत्र अमेरिकी न्याय विभाग को भेजा। इस पत्र में एजेंसी ने अमेरिकी निजी जासूसी कंपनी फेयरफैस के प्रमुख माइकल हर्शमैन ने जुड़ी जानकारी की मांग की है।

2017 में हर्शमैन ने दावा किया था कि तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी गुप्ते में थे जब उन्होंने स्विस बैंक खाते मॉन्ट ब्लांक का पता लगाया, जहां बोफोर्स से रिश्त की रकम कांथित रूप से जमा की गई थी। हर्शमैन ने यह भी कहा था कि उस समय की सरकार ने उनकी जांच को नाकाम कर दिया था।

सीबीआई ने पहली बार अक्टूबर 2024 में दिल्ली की अदालत से संपर्क किया था, जिसमें उन्हें अमेरिकी अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करने के लिए जुर्माने देने का अनुरोध किया था। यह कदम उस समय उत्तराधीन था कि जब हर्शमैन ने भारतीय एजेंसियों के साथ सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की थी।

क्या है बोफोर्स घोटाला?

बोफोर्स घोटाला को स्वीडिश रेडियो ने उजागर किया था। यह 1989 के चुनावों में राजीव गांधी की हार का एक प्रमुख कारण बना था। हालांकि 2004 में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ रिश्त के आरोप को खारिज कर दिया था, लेकिन इस भारत और स्वीडन दोनों को चाँका दिया था जब उन्होंने होविल्यर डील में रिश्त के भुगतान का खुलासा किया था।

सीबीआई ने 1990 में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी और 1999 और 2000 में चार्जरीट डायलिंग की थी। राजीव गांधी को बरी करने के बाद विशेष अदालत ने अन्य आरोपियों, जिनमें हिंदुआ बंधु भी शामिल थे, के खिलाफ सभी आरोप हटा दिए थे। 2011 में क्रांतीयों को भी बरी कर दिया गया। अदालत ने सीबीआई की याचिका को मंजूरी दी और उसकी खिलाफ की गई कार्रवाई को वापस ले लिया।

क्रांतीयों पर ध्यान तब फिर से केंद्रित हुआ जब यूपी सरकार ने ब्रिटेन में उसके बैंक खाते से लाखों डॉलर की रिलायंज चुनौती देने से इनकार कर दिया। 1987 में स्वीडिश पल्किं पल्किं बॉडकास्टर ने भारत और स्वीडन दोनों को चाँका दिया था जब उन्होंने होविल्यर डील में रिश्त के भुगतान का खुलासा किया था।

सीबीआई ने 1990 में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी और 1999 और 2000 में चार्जरीट डायलिंग की थी। राजीव गांधी को बरी करने के बाद विशेष अदालत ने अन्य आरोपियों, जिनमें हिंदुआ बंधु भी शामिल थे, के खिलाफ सभी आरोप हटा दिए थे। 2011 में क्रांतीयों को भी बरी कर दिया गया। अदालत ने सीबीआई की याचिका को मंजूरी दी और उसकी खिलाफ की गई कार्रवाई को वापस ले लिया।

क्या है बोफोर्स घोटाला?

बोफोर्स घोटाला को स्वीडिश रेडियो ने उजागर किया था। यह 1989 के चुनावों में राजीव गांधी की हार का एक प्रमुख कारण बना था। हालांकि 2004 में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ रिश्त के आरोप को खारिज कर दिया था, लेकिन इस भारत और स्वीडन दोनों को चाँका दिया था जब उन्होंने होविल्यर डील में रिश्त के भुगतान का खुलासा किया था।

सीबीआई ने 1990 में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी और 1999 और 2000 में चार्जरीट डायलिंग की थी। राजीव गांधी को बरी करने के बाद विशेष अदालत ने अन्य आरोपियों, जिनमें हिंदुआ बंधु भी शामिल थे, के खिलाफ सभी आरोप हटा दिए थे। 2011 में क्रांतीयों को भी बरी कर दिया गया। अदालत ने सीबीआई की याचिका को मंजूरी दी और उसकी खिलाफ की गई कार्रवाई को वापस ले लिया।

क्या है बोफोर्स घोटाला?

बोफोर्स घोटाला को स्वीडिश रेडियो ने उजागर किया था। यह 1989 के चुनावों में राजीव गांधी की हार का एक प्रमुख कारण बना था। हालांकि 2004 में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ रिश्त के आरोप को खारिज कर दिया था, लेकिन इस भारत और स्वीडन दोनों को चाँका दिया था जब उन्होंने होविल्यर डील में रिश्त के भुगतान का खुलासा किया था।

सीबीआई ने 1990 में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी और 1999 और 2000 में चार्जरीट डायलिंग की थी। राजीव गांधी को बरी करने के बाद विशेष अदालत ने अन्य आरोपियों, जिनमें हिंदुआ बंधु भी शामिल थे, के खिलाफ सभी आरोप हटा दिए थे। 2011 में क्रांतीयों को भी बरी कर दिया गया। अदालत ने सीबीआई की याचिका को मंजूरी दी और उसकी खिलाफ की गई कार्रवाई को वापस ले लिया।

क्या है बोफोर्स घोटाला?

बोफोर्स घोटाला को स्वीडिश रेडियो ने उजागर किया था। यह 1989 के चुनावों में राजीव गांधी की हार का एक प्रमुख कारण बना था। हालांकि 2004 में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ रिश्त के आरोप को खारिज कर दिया था, लेकिन इस भारत और स्वीडन दोनों को चाँका दिया था जब उन्होंने होविल्यर डील में रिश्त के भुगतान का खुलासा किया था।

सीबीआई ने 1990 में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी और 1999 और 2000 में चार्जरीट डायलिंग की थी। राजीव गांधी को बरी करने के बाद विशेष अदालत ने अन्य आरोपियों, जिनमें हिंदुआ बंधु भी शामिल थे, के खिलाफ सभी आरोप हटा दिए थे। 2011 में क्रांतीयों को भी बरी कर दिया गया। अदालत ने सीबीआई की याचिका को मंजूरी दी और उसकी खिलाफ की गई कार्रवाई को वापस ले लिया।

क्या है बोफोर्स घोटाला?

बोफोर्स घोटाला को स्वीडिश रेडियो ने उजागर किया था। यह 1989 के चुनावों में राजीव गांधी की हार का एक प्रमुख कारण बना था। हालांकि 2004 में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ रिश्त के आरोप को खारिज कर दिया था, लेकिन इस भारत और स्वीडन दोनों को चाँका दिया था जब उन्होंने होविल्यर डील में रिश्त के भुगतान का खुलासा किया था।

क्या है बोफोर्स घोटाला?

बोफोर्स घोटाला को स्वीडिश रेडियो ने उजागर किया था। यह 1989 के चुनावों में राजीव गांधी की हार का एक प्रमुख कारण बना था। हालांकि 2004 में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ रिश्त के आरोप को खारिज कर दिया था, लेकिन इस भारत और स्वीडन दोनों को चाँका दिया था जब उन्होंने होविल्यर डील में रिश्त के भुगतान का खुलासा किया था।

क्या है बोफोर्स घोटाला?

बोफोर्स घोटाला को स्वीडिश रेडियो ने उजागर किया था। यह 1989 के चुनावों में राजीव गांधी की हार का एक प्रमुख कारण बना था। हालांकि 2004 में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ रिश